International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
May-June- 2020, Volume-7, Issue-3
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

भारत और पड़ौसी देश– मोदी जी की पड़ोसी नीति : मोदी के कार्यकाल में बड़ा सुधार

1. डॉ० अनुजा रानी गर्ग (एसोसिएट प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष), शोध निर्देशिका, राजनीति विज्ञान विभाग शहीद मंगल पाण्डे राजकीय महिला स्नातकोतर महाविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ०प्र०).

2. राकेश कुमार, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग शहीद मंगल पाण्डे राजकीय महिला स्नातकोतर महाविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ०प्र०).

1.1 प्रस्तावना–

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विदेश नीति के प्रश्न पर अपर्णा पाण्डे ने कहा, "मेरा मानना है कि हमारी विदेश नीति वर्षों से सततता पर जोर देती आई है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसमें उत्साह और जुनून झोंकने का काम किया है। आखिरी बार विदेश नीति के प्रति इस प्रकार का जुनून पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू में देखा गया था, जो कि यह मानते थे कि जितना अधिक भारत दुनिया के देशों से जुड़ा रहेगा, उतना ही उसे फायदा होगा। भारत को बस इसके बारे में जानने के लिए लोगों की आवश्यकता थी।" देश में वर्तमान व्यापार और निवेश पर अपर्णा ने कहा, "मोदी चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि हमारे पास क्षमता है। हमारे पास सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेना है। हम दुनिया से सेवाएँ सिर्फ माँग ही नहीं रहे हैं बल्कि हम सेवाएँ प्रदान भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को एक बड़े बाजार, एक बड़े देश, एक मित्र और सहयोगी के रूप में पेश करते हैं, जिसके साथ कोई भी व्यवसाय कर सकता है।"

1.1.2 मोदी के कार्यकाल में बड़ा सुधार

अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, "हालाँकि, नरेंद्र मोदी की समस्याएँ जस की तस हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई देश में आए और निवेश करे, तो आपको इसे पूरी तरह से खोलना होगा। इस तरह से मोदी के कार्यकाल में GST दिवालिया कानून (इन्साल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) जैसे बेहतरीन सुधार तो

हुए हैं लेकिन 'भूमि, मजदूर और पूँजी' जैसे व्यवसाय के तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक गहराई से खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है।" उन्होंने कहा कि भारत देश में एक दूसरी बड़ी समस्या सैन्य है, जिसे कम से कम दो दशक पहले आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी। भारतीय सेना का निर्माण आज के लिए नहीं बल्कि 2050 के लिए होना चाहिए। अपर्णा ने बताया कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर हमारी खरीद प्रक्रिया और निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी होने के साथ जटिल और राजनीतिक भी हैं।

पाकिस्तान हमेशा भारत देश की समझौते की नीति का विरोध करता आया है पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्धों पर पर अपर्णा ने कहा कि यह बातचीत किसी भी मोड़ पर पहुँचती नहीं दिखती है। भारत ने हमेशा समझौते की बात की है, चाहे शिमला समझौता हो या फिर 1960 का सिन्धु जल समझौता हो या फिर 1988 का नाभिकीय सुविधाओं का समझौता रहा हो, पाकिस्तान हमेशा समझौते की नीति का विरोध करता है। पाकिस्तान कारगिल जैसे पीठ में चाकू घोंपने वाले काम कर चुका है। भारत ने फिर भी हमेशा समझौते की राह पकड़ी लेकिन फिर भी मुंबई हमले जैसे हादसे हुए। मोदी जी ने आसियान देशों के साथ दोस्ती को मजबूत किया है।

1.1.3 रायसीना संवाद 2019

रायसीना डायलाग भारत का प्रमुख वार्षिक भू–राजनीतिक और भू–स्थानिक सम्मेलन है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के हितधारक, राजनेता, पत्रकार उच्चाधिकारी तथा उद्योग एवं व्यापार जगत से सम्बंधित प्रतिनिधि एक मंच पर अपने विचार साझा करते हैं। रायसीना डायलाग का चौथा संस्करण मंगलवार (जनवरी 8, 2019) को शुरू हुआ। इसमें 93 देशों के वक्ताओं ने भाग लिया। यह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की संयुक्त पहल है। रायसीना डायलाग का मुख्य उद्देश्य एशियाई एकीकरण एवं शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय की संभावनाओं तथा अवसरों की तलाश करना है। वर्ष 2019 के रायसीना सम्मेलन का मुख्य विषय था"।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों के चलते ही भारत एक वैश्विक नेता बनकर उभरा

है। उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति पहले भारत के मंत्र पर ही आधारित है। वैश्विक परिदृश्य से बाहर होने की बात अब भूल जाइए। भारत अब कुछ मुद्दों पर वैश्विक कथन निर्धारित कर रहा है। नरसापुरम के एक कार्यकर्ता के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसा मेरी वजह से नहीं है। बल्कि देश के हरेक व्यक्ति के कारण है जिसने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है। देशहित और जनहित ही भारत की विदेश नीति की दशा और दिशा तय कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जी–20 सम्मेलन में शामिल होते हुए जब उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए विश्व को काले धन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की तो यह मुद्दा कई वैश्विक मंचों पर उठा है। उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि रीयल टाइम में काले धन की सूचना देने को लेकर कई देशों के साथ भारत ने समझौते किए हैं। मोदी ने कहा कि काला धन वापस लाया जाएगा और इसे रखने वालों को भी सजा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पिछले बीस सालों में यह पहली बार हुआ है कि भारत विदेश प्रत्यक्ष निवेश (फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट) में चीन को भी पीछे छोड़ चुका है। हमारी जापान के साथ 75 अरब डालर की करेंसी का स्वैप समझौता करने से साफ है कि देशों के बीच दोस्ती भारी आर्थिक लाभ भी देती हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को गेमचेंजर करार देते हुए कहा कि अब गरीब लोग धन की कमी के चलते इलाज से वंचित नहीं रहेंगे।

1.2 संयुक्त राष्ट्र में भारत

भारत ने 100,000 सैन्य और पुलिस कर्मियों को चार महाद्वीपों भर में संयुक्त राष्ट्र के पैंतीस शांति अभियानों में सेवा प्रदान की है।

1.2.1 प्रत्यर्पण संधियाँ

जनवरी 2014 तक भारत 37 देशों के साथ अपराधियों के प्रत्यार्पण की संधि कर चुका है, जिनकी सूची इस प्रकार है, –

1.2.2 सीमावर्ती व निकटवर्ती देश

2014 में भारत के नए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करके पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्तों में नई जान फूँक दी। इस घटना को वृहत ''प्रमुख राजनयिक घटना के रूप में भी देखा गया। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के साथ एक तनाव भरा संबंध है और दोनों देशों के बीच चार बार युद्ध हुआ है, 1947, 1965, 1971 और 1999 में कश्मीर विवाद इन युद्धों का प्रमुख कारण था।

1.2.3 भारत–नेपाल सम्बन्ध

भारत और नेपाल अच्छे पड़ोसी है। भारत और नेपाल के साथ रोटी–बेटी का सम्बन्ध है। इस बात का उदाहरण उस समय देखने को मिला था जब नेपाल में भारी भूकम्प आया था तब सर्वप्रथम भारत ने वहाँ पर रहात व बचाव कार्य शुरू किया था बल्कि नेपाल को फिर से बसाने के लिये भारत ने कई योजना चलाई।

1.2.4 भारत–भूटान सम्बन्ध

भूटान भारत का सबसे विश्वसनीय व शांतिरक्षक पड़ोसी देश है। भूटान के रक्षा का प्रभार भारत पर है। भूटान की विदेश नीति भारत तय करता है। भारतीय फौज मे भूटान और नेपाल के लोग भी शामिल होते है। भारत और म्यांमार दोनों पड़ोसी हैं। इनके संबन्ध अत्यन्त प्राचीन और गहरे हैं और आधुनिक इतिहास के तो कई अध्याय बिना एक–दूसरे के उल्लेख के पूरे ही नहीं हो सकते। आधुनिक काल में 1937 तक बर्मा भी भारत का ही भाग था और ब्रिटिश राज के अधीन था। बर्मा के अधिकतर लोग बौद्ध हैं और इस नाते भी भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध बनता है। पड़ोसी देश होने के कारण भारत के लिए बर्मा का आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक महत्व भी है।

1.2.5 श्रीलंका और मालदीव

1980 के दशक में भारत दो पड़ोसी देशों के निमंत्रण पर, सेना के द्वारा संक्षिप्त सैन्य हस्तक्षेप किया,

एक श्रीलंका में और दुसरा मालदीव में। मालदीव को भारत का दक्षिण का प्रहरी कहा जाता है। चीन के साथ 1962 के भारत – चीन युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के बाद भारत और सोवियत संघ के साथ सैन्य संबंधों मे काफी बडोतरी हुई। 1960 के दशक के अन्त में, सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरी थी।

1.3 शेष एशिया–प्रशांत व आस्ट्रेलिया 1.3.1 आस्ट्रेलिया

सितंबर 2014 में आस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री टोनी एबाट भारत की यात्रा पर आए। भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की यह प्रथम राजकीय यात्रा थी। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच असैन्य नाभिकीय उर्जा सहयोग समझौता हुआ जिसके तहत आस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम निर्यात करेगा। इस दौरान एक महत्वपूर्ण व्यक्तव्य में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए।

1.3.2 भारत–जापान सम्बन्ध

भारत और जापान के सम्बन्ध हमेशा से काफी मजबूत और स्थिर रहे हैं। जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी जापान की शाही सेना ने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिन्द फौज को सहायता प्रदान की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद से भी अब तक दोनों देशों के बीच मधुर सम्बन्ध रहे हैं। जापान की कई कम्पनियाँ जैसे कि सोनी, टोयोटा और होंडा ने अपनी उत्पादन इकाइयाँ भारत में स्थापित की हैं और भारत की आर्थिक विकास में योगदान दिया है। इस क्रम में सबसे अभूतपूर्व योगदान है वहाँ की मोटर वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी का जो भारत की कंपनी मारुति सुजुकी के साथ मिलकार उत्पादन करती है और भारत की सबसे बड़ी मोटर कार निर्माता कंपनी है। होंडा कुछ ही दिनों पहले तक हीरो होंडा (अब हीरो मोटोकार्प) के रूप में हीरो कंपनी के पार्टनर के रूप में कार्य करती रही है जो तब दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल विक्रेता कंपनी थी।

जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे के आर्क आफ फ्रीडम सिद्धांत के अनुसार यह जापान के हित में है कि वह भारत के साथ मधुर सम्बन्ध रखे खासतौर से उसके चीन के साथ तनाव पूर्ण रिश्तों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो। इसके लिये जापान ने भारत में अवसंरचना विकास के कई प्रोजेक्ट का वित्तीयन किया है और इनमें तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है दिल्ली मेट्रो रेल का निर्माण।

भारत की ओर से भी चीन के साथ रिश्तों और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जापान को काफी महत्व दिया गया है। मनमोहन सिंह की सरकार की पूर्व की ओर देखो नीति ने भारत को जापान के साथ मधुर और पहले से बेहतर सम्बन्ध बनाने की ओर प्रेरित किया है। दिसंबर 2006 में भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दुरान हस्ताक्षरित भारत–जापान सामरिक एवं वैश्विक पार्टनरशिप समझौता इसका ज्वलंत उदहारण है। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच 2007 से लगातार सहयोग मजबूत हुए हैं, और दोनों की रक्षा इकाइयों और सेनाओं ने कई संयुक्त रक्षा अभ्यास किये हैं। अक्टूबर 2008 में जापान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत वह भारत को कम ब्याज दरों पर 450 अरब अमेरिकी डालर की धनराशि दिल्ली–मुम्बई हाईस्पीड रेल गलियारे के विकास हेतु देगा। विश्व में यह जापान द्वारा इकलौता ऐसा उदाहरण है जो भारत के साथ इसके मजबूत आर्थिक रिश्तों को दर्शाता है।

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने जनवरी 2014 में भारत की सपत्नीक यात्रा की जिसके दौरान वे इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गये थे। इसके बाद मनमोहन सिंह जी के साथ हुई शिखर बैठक दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच 2006 की शुरुआत के बाद आठवीं शिखर बैठक थी। इस बैठक में जापान ने भारत को विभिन्न परियोजनाओं के लिये 200 अरब येन (लगभग 122 अरब रुपये) का ऋण देने की पेशकश की और हाई स्पीड रेल, रक्षा, मेडिकल केयर, औषधि निर्माण और कृषि तथा तापीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की भी पेशकश की। भारत जापान श्रीलंका के पूर्वी भाग में त्रिंकोमाली में तापीय विद्युत संयत्र निर्माण में भी भागीदारी करने वाले हैं। इससे पहले नवंबर–दिसंबर 2013 में जापानी

सम्राट आकिहितो और महारानी मिचिको ने भारत की यात्रा संपन्न की थी। प्रोटोकाल के विपरीत सम्राट को हवाईअड्डे पर लेने स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गये थे जो भारत जापान रिश्तों की प्रगाढ़ता दर्शाता है। वर्तमान समय में भारत जापान द्विपक्षीय व्यापर लगभग 14 अरब डालर का है जिसे बढ़ा का 25 अरब डालर करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जापान का भारत में लगभग 15 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी है।

1.4 राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंध

नई दिल्लीः नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। मोदी सरकार ने अपने इस कार्यकाल के दौरान विदेश नीति पर खूब ध्यान दिया और इस बात की पूरी कोशिश की कि हर छोटे–बड़े मुल्क से उसके रिश्ते बेहतर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की शुरूआत एक नए कूटनीतिक अंदाज से हुई। उन्होंने एक नई पहल की जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ। उनके शपथग्रहण समारोह में सार्क देशों और मारीशस के शासनाध्यक्ष शामिल हुए। सबसे ज्यादा ध्यान खींचा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इसे संबंधों के एक नए युग की शुरुआत का संकेत माना गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मोदी के न्यौते पर भारत आना पड़ा। हालांकि नवाज की भारत यात्रा का कोई कूटनीतिक लाभ तो नहीं हुआ लेकिन ऐसा कर मोदी सरकार ने वार्ता की गेंद पाकिस्तान के पाले में डाल दी। ऐसा लगने लगा कि भारत पाक की सचिव वार्ता से दोनों देशों के रिश्ते को मजबूती मिल सकती है। लेकिन दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को बुलाए जाने पर विरोध जताते हुए विदेश सचिव स्तर की प्रस्तावित वार्ता को रद्द कर दिया। भारत के मुताबिक ये उसके अंदरूनी मामलों में साफ दखल है। पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए ये नई लक्ष्मण रेखा शासन के शीर्ष से खींची गई। पाकिस्तान के साथ रिश्तों की गाड़ी पटरी पर आने से पहले ही उतर गई। सरहद पर जारी गोलेबारी में तमाम उम्मीदें खाक हो गई हैं। बाहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने साफ किया है कि विदेश नीति में पड़ोसियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि मोदी ने यह जरूर कह दिया

कि हम पाकिस्तान से निराश हुए क्योंकि उसने बातचीत का मजाक बनाया। उन्होंने यह भी संदेश दिया कि वह पाकिस्तान से साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं।

पाकिस्तान भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने पर कभी गंभीर नहीं रहा लेकिन मोदी ने नेपाल जैसे छोटे मुल्क के साथ भी रिश्ते बेहतर करने के लिए गंभीरता बरती। बीते 17 साल में नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो द्विपक्षीय वार्ता के लिए काठमांडू गए। नेपाल की संसद में उनके भाषण को गौर से सुना गया। बतौर पीएम मोदी की विदेश यात्रा को लेकर जब विदेश मंत्रालय की तरफ से सूची तैयार की गई थी, तो उसमें भूटान का नाम सबसे ऊपर था। उस वक्त मोदी की विदेश यात्रा को लेकर चीन, जापान और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में भूटान को दी गई अहमियत पर चर्चा जोरदार हुई। लेकिन अपनी यात्रा के दूसरे और आखिरी दिन मोदी ने भूटान की संसद के संयुक्त अधिवेशन को हिंदी में संबोधित कर इतिहास बना डाला। साथ ही पीएम मोदी की ये यात्रा इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गई, क्योंकि ये पहला मौका था जब, किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने दूसरे देश की सांसद को हिंदी में संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान न सिर्फ दोनों देशो के बीच मजबूत रिश्तों का हवाला दिया, बल्कि दोनों देशों के सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करते हुए आपसी सहयोग और बढ़ाने पर भी जोर दिया। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए पड़ोसी देश भूटान को अहमियत दी।

प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील जाना और सौ अरब डालर के ब्रिक्स बैंक की स्थापना का फैसला भी एक अहम कदम रहा। दूसरी तरफ चीन भी नई सरकार से रिश्ते बनाने को उत्सुक है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन ने अपने विदेशमंत्री को विशेष दूत बतौर भारत भेजा। चीन के राष्ट्रपति भी सितंबर में भारत का दौरा करेंगे। मोदी इस महीने के आखिर में जापान का दौरा करेंगे। यह दौरा भारत के लिए अहम होगा क्योंकि जापान की तकनीक के वह कायल है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से दोनों देशों के अच्छे संबंध और मजबूत होंगे तथा पारस्परिक व्यापार सहयोग और आर्थिक आदान–प्रदान बढ़ेगा। क्योंकि भारत और जापान के संबंध हमेशा

से बहुत अच्छे रहे हैं और ये समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, मोदी की इस यात्रा से इन 'स्वस्थ्य संबंधों' में में और मजबूती आएगी। जानकारों के मुताबिक मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण यादगार यात्रा होगी। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि मोदी कारोबार को महत्व देने वाले नेता है, उनकी इस यात्रा से भारत जापान संबंध और मजबूत होगा और व्यापार एवं कारोबार में सहयोग के नये क्षितिज खुलेंगे। मोदी की जापान यात्रा बहुराष्ट्रीय कंपनियों विशेष तौर पर जापानी कंपनियों के लिए निवेश अनुकूल रखने की बेहतर बुनियाद साबित हो सकती है।

उनकी यह यात्रा सामरिक और वैश्विक सहयोगों को नए स्तर पर ले जाए जाने की आकांक्षाओं के बीच हो रही है। मोदी की चार दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा, असैन्य परमाणु, ढ़ांचागत विकास और 'रेयर अर्थ मिनरल्स' के अलावा व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना आदि मुख्य प्राथमिकताएं होंगी। इस यात्रा पर मोदी जापानी प्रधानमंत्री शिजों एबे से विस्तृतत वार्ता करगें और अन्य नेताओं से भी मिलकर सामरिक तथा वैश्विक साझेदारी को आगे ले जाने के तरीकों पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान रखा एवं असैन्य परमाणु संबंधी कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावनाएं हैं।

हालांकि आज की तारीख में कारोबार और निवेश के लिहाज से रूस बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, लेकिन वह आज भी भारत का प्रमुख शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश है और मोदी इस रिश्ते में बदलाव नहीं करना चाहेंगे। जबकि चीन को आमतौर पर भारत का प्रमुख भू–सामरिक विरोधी माना जाता है। आज चीन, भारत का मुख्य कारोबारी सहयोगी भी है इसलिए सभी कुछ सुरक्षा और युद्ध के लिहाज से ही नहीं सोचा जा सकता है। लेकिन जब चीन की बात आती है तो हमें सोचना होगा कि आर्थिक और सैन्य दृष्टि से भारत कमजोर है और मोदी कितने ही बड़े राष्ट्रवादी क्यों ना हों और उन्होंने दूसरे दलों के नेताओं की इस बात को लेकर कितनी ही आलोचना की हो कि वे चीन के दुस्साहस को अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन खुद मोदी भी पेइचिंग से लड़ाई मोल लेना नहीं चाहेंगे। चीन को एक वैश्विक शक्ति उसकी आर्थिक ताकत के कारण

माना जाता है और इस कारण से मोदी चाहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं पिछले 100 दिनों में नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति का मर्म समझा है और विदेश नीति के मोर्चे पर वह बेहद कामयाब रहे हैं।

दुनिया के दिग्गज देशों की विदेश नीति के विषय में यह बात एकदम सही है कि उनकी इस नीति में सरकारों के बदलने के साथ बहुत बदलाव देखने को नहीं मिलते। हालांकि भारत में यह रुझान कुछ बदला है। यहां 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से विदेश नीति में एक नया उभार देखने का मिला है। हालांकि वैश्विक शक्ति अनुक्रम में ऊपर बढ़ते किसी देश के लिए ऐसा बदलाव बहुत स्वाभाविक भी है। भारतीय विदेश नीति में आए इस बदलाव के तत्व को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करीब एक साल पहले अपने एक भाषण में व्यक्त करने के साथ ही हल में अपनी किताब में भी रेखांकित किया है। जयशंकर का कहना है कि अब कहीं अधिक आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारत एक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। इसमें उन्होंने यह दलील भी दी कि ऐसा देश जो एक दिन दुनिया की बड़ी शक्ति बनने की हसरत रखता हो, वह विवादित सीमाओं, विखंडित क्षेत्र और अवसरों को पर्याप्त रूप से न भुना पाने की स्थिति को कायम नहीं रख सकता।

कुल मिलाकर बदलते वैश्विक परिदृश्य में हम ठहरे हुए नहीं रह सकते। जयशंकर का यह भाषण अब एक केंद्रीय बिंदु बन गया है। सामरिक विश्लेषकों की एक बिरादरी जो भारतीय विदेश नीति में निरंतरता एवं उसकी उपयोगिता का बखान करते नहीं थकती, उसे जयशंकर का भाषण आईना दिखाने का काम करता है। वह दो–टूक लहजे में कहते हैं कि विगत सात दशकों में भारतीय विदेश नीति का बहीखाता मिली–जुली तस्वीर ही दिखाता है। वह यह भी रेखांकित करते हैं कि विदेश नीति में निरंतरता अतिरेक भी हो सकती है।

वर्ष 2019 में और भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आए प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपने महत्वाकांक्षी एजेंडे का तुरंत आगाज किया। विदेश मंत्री के रूप में किसी

कद्दावर नेता के बजाय उन्होंने पूर्व राजनयिक एस जयशंकर लाकर तमाम लोगों को चौंका दिया। जयशंकर की नियुक्ति ने यह दर्शाया कि वैश्विक स्तर पर उथलपुथल को लेकर मोदी खासे संजीदा हैं और इस हलचल में नैया पार लगाने के लिए उन्हें किसी अनुभवी दिग्गज की दरकार है। जयशंकर न केवल मोदी की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हैं, बल्कि उन्हें परंपराओं के बजाय पेशेवर रुख भी प्रदान करते हैं। मोदी सरकार द्वारा जम्मू–कश्मीर में अनुच्छेद 370 के मसले पर लिए गए फैसले से उपजी परिस्थितियों में वैश्विक मोर्चे पर जयशंकर की इन क्षमताओं की आवश्यकता और अधिक महसूस हुई। तब भारत ने पूरी दुनिया और खासतौर से दिग्गज देशों को साधने का काम किया। वैश्विक स्तर पर अपने कद को बढ़ाने और हितों की पूत के लिए नई दिल्ली ने अंतरराष्ट्रीय तंत्र में प्रभावी तमाम पक्षों के साथ विभिन्न मोर्चों पर सक्रियता भी बढ़ाई है। यह कसौटी दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसियों से लेकर हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिम एशियाई देशों तक पर लागू होती है। जब यूरोपीय संघ अपनी भू–राजनीतिक पैठ को बढ़ाने में जुटा है, तब यूरोपीय देशों के साथ भी भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री के साथ भारतीय विदेश और रक्षा मंत्री की बातचीत से भी यही साबित होता है।

भारत का बढ़ता कद बदलते वैश्विक ढांचे में अपने प्रमुख साझेदारों के साथ नई दिल्ली के रवैये को नए सिरे से तय कर रहा है। जहां भारत में कुछ वर्ग अभी भी गुटनिरपेक्षता के हिमायती बने हुए हुए हैं, वहीं मोदी के नेतृत्व में नई दिल्ली गुटनिरपेक्षता से इतर अलग रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारतीय विदेश नीति में इस रुख की लंबे अर्से से प्रतीक्षा की जा रही थी और साझेदारी से कन्नी काटने के बजाय उनसे लाभ उठाने की दिशा में आगे बढना देश के हित में है।

यही कारण है कि आज भारत वैचारिक बैसाखियों से मुक्त होकर अपनी द्विपक्षीय साझेदारियों को अपने हिसाब से परिभाषित करने की बेहतर स्थिति में है।

भारत की विदेश नीति के उद्भव में चीन का उभार एक निर्णायक पहलू है। इन दिनों चीन के उभार और उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर व्यापक चर्चा हो रही है। इससे इन्कार नहीं कि चीन अंतरराष्ट्रीय ढांचे

को प्रभावित कर रहा है। वह हर मोर्चे पर सक्रिय है और वैश्विक ढांचे को चुनौती दे रहा है। वह खुद को नए वैश्विक आथक ढांचे के संरक्षक के तौर पर पेश करने का भी प्रयास करता है। सबसे अधिक आबादी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चीन वैश्विक ढांचे में और प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए तत्पर दिखाई देता है। 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी के बाद से अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी भूमिका को लेकर चीनी नेतृत्व और मुखर हुआ है। फिर भी चीन में तमाम चुनौतियां कायम हैं। उसकी प्रति व्यक्ति आय अभी भी विकसित देशों के मुकाबले खासी कम है। साथ ही बढ़ती विषमता और बूढ़ी होती आबादी भी उसके लिए समस्याएं बनी हुई हैं। चीन के लिए आथक समृद्धि की निरंतरता बेहद आवश्यक है।

शी चिनफिंग से पहले चीनी नेता चीन की गरीब या विकासशील देश के रूप में चर्चा कर लिया करते थे, लेकिन शी चीन को महाशक्ति मानते हैं। शी वास्तव में माओत्से तुंग के बाद चीन के सबसे शक्तिशाली नेता बन गए हैं। चीनी संविधान ने उनके आजीवन सर्वोच्च नेता बने रहने का रास्ता भी साफ कर दिया है। चीन भले ही बहुध्रुवीय विश्व की बात करता हो, लेकिन वह एशिया में एकछत्रधाक चाहता है। हाल के वर्षों में सामुद्रिक दावे और धौंस के जरिये उसने यही साबित करने की कोशिश की है कि इस क्षेत्र और उससे परे उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं। चीनी युद्धोन्माद का तोड़ निकालने में क्षेत्रीय शक्तियां बहुत कमजोर हैं। चीन के सामने आसियान कागजी शेर ही साबित होता है। चीन की बांटो और राज करो की नीति ने दक्षिणपूर्व एशिया में किसी कारगर एकता को खंडित करने का ही काम किया है। हिंद–प्रशांत क्षेत्र में, जहां चीन और भारत, दोनों उभर रहे हैं, अतीत की तुलना में दोनों देशों के बीच टकराव के मामले भी बढ़े हैं। हिमालयी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच तल्खी इसी रुझान की पुष्टि करने के साथ ही इस क्षेत्र में नई भू–राजनीतिक वास्तविकता को दर्शाती है। इसका सार यही है कि भविष्य में हिंद–प्रशांत क्षेत्र के लिए संघर्ष की धार और तेज होगी।

2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के शपथग्रहण समारोह में सभी सार्क देशों को न्यौता भेजा गया था, और

उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी समारोह में शामिल हुए थे। पड़ोसी देशों को न्यौते से यह साफ था कि मोदी सरकार का विदेश नीति पर विशेष ध्यान रहेगा। 2019 में जब पीएम मोदी ने शपथ ली, उस वक्त भी पड़ोसी मुल्कों को न्यौता भेजा गया। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इस बार निमंत्रण नहीं भेजा गया। वजह साफ थी, पुलवामा आतंकी हमले के साये में यह दुनिया के सामने था कि पाक समर्थित आतंकवाद पर इमरान खान सरकार रोक नहीं लगा पाई।

मोदी सरकार 2.0 के पहले 100 दिनों में कश्मीर मुद्दा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का मजबूती से अपनी बात रखना छाया रहा। नतीजा पूरी दुनिया यह मानती है कि संविधान में बदलाव और अनुच्छेद 370 हटाना भारत का अंदरूनी मामला है। साथ ही इस मुद्दे पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। कश्मीर पर 5 अगस्त को लिए गए फैलसे के बाद पाकिस्तान बौखला गया था। 370 को हटाने के ऐतिहासिक फैसले से पाक सरकार सकते में आ गई और कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की पुरजोर तैयारी करने लगी। लेकिन पाकिस्तान यह नहीं जानता था कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसे मुंह की खानी पड़ेगी।

1.5 सुरक्षा परिषद में भारत को बड़ी सफलता

भारत के कदम से बोखलाए पाकिस्तान ने अपने सबसे करीबी दोस्त चीन से मदद मांगी। इसके बाद बीजिंग कश्मीर मुद्दे को सुरक्षा परिषद में उठाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन चीन–पाक की कोशिशों पर तब पानी फिर गया जब सुरक्षा परिषद के 15 में से 14 सदस्यों ने कश्मीर मुद्दे पर कोई बयान जारी करने से मना कर दिया। साथ ही इस मुद्दे पर सिर्फ अनऔपचारिक चर्चा हुई और न सुरक्षा परिषद ने कश्मीर मुद्दे में दखल देने से इंकार कर दिया। भारत की इस कामयाबी के पीछे एक मजबूत रणनीति थी। भारत के रुख का दुनिया भर में इसलिए भी समर्थन हुआ, क्योंकि पिछले एक महीने में

घाटी से किसी बड़ी हिंसक घटना या किसी नागरिक के हताहत होने की खबर नहीं आई। फैसले से पहले सुरक्षाबलों की तैनाती की वजह से कानून–व्यवस्था बनाये रखने में मोदी सरकार को पूरी कामयाबी

मिली। जैसा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, पाकिस्तान को हिंसा फैलाने की कोशिशों के बावजूद न एक भी गोली चली, न ही किसी नागरिक की जान गई। इमरान खान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुंह की खानी पड़ी।इमरान खान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुंह की खानी पड़ी। दुनियाभर में भारत के रुख को समर्थन इस लिए भी मिला, क्योंकि 5 अगस्त के बाद विदेश मंत्रालय ने न सिर्फ 5 देशों यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को अपने फैसले की जानकारी दी, बल्कि इस्लामिक देशों को भी नई दिल्ली ने हालात से अवगत कराया।

1.5.1 इस्लामिक देशों का मिला समर्थन

जो इस्लामिक देश कभी कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते थे, आज वो भारत का मजबूती से समर्थन करते नजर आए। पीएम मोदी की विदेश यात्राओं से भारत और इस्लामिक वर्ल्ड की दूरियां और कम हुई। यही वजह है कि आज इस्लामिक देश भारत को एशिया में एक मजबूत देश मानते हैं। कश्मीर पर सबसे पहले बयान में इसे भारत का अंदरूनी मामला बताया। वहीं, मालदीव ने भी भारत के रुख का समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी के बहरीन दौरे पर भी वो देश भारत के साथ खड़ा नजर आया। इमरान खान की बेचैनी इस बात से भी साफ हो जाती है कि राष्ट्र के नाम अपने संदेश में पाक पीएम ने यह माना था कि अब वो दुनिया में अकेला पड़ गया है और आज इस्लामिक देश भी उसके साथ नहीं हैं।

1.5.2 संबंधों को मजबूत करने पर पीएम को सम्मान

अन्य देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी के योगदान को सराहा भी गया। बहरीन और रूस ने पीएम मोदी को सबसे बड़े नागरिक सम्मानों से नवाजा। पहले 100 दिनों में पीएम मोदी को जायेद मैडल, बहरीन के किंग हमाद आर्डर और रूस के आर्डर आफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा गया है। हालांकि मोदी ने भी अपने चुनावी वादों को पूरा करते हुए कई काम शुरु कर दिये है। इसलिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार मानी जाने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी विकसित मुल्कों

और बड़े निवेशकों की दिलचस्पी लाजमी है। मोदी सरकार के साथ संपर्को की पहल में दुनिया के कई मुल्क 100 स्मार्ट सिटी, हीरक चतुर्भुज रेल परियोजना, बुलेट ट्रेन समेत ढांचागत विकास की बड़ी परियोजनाओं में निवेश व हिस्सेदारी के लिए अपनी दावेदारियां पेश कर चुके हैं। मोदी के सामने इन देशों से संबंध सुधारने के पीछे भारत में अर्थव्यस्था को मजबूत करना, निवेश को बढ़ावा देना और कई सालों से जारी सीमा विवाद को बातचीत के जरिये सुलझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में वाहवाही लूटने में कामयाब रहे हैं उन्होंने आतंकवाद को लेकर जिस तरह से चिंता जाहिर की है उससे कई देश मोदी का समर्थन करते नजर आये।

1.6 पाकिस्तान के साथ संबंध

भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंध को हमेशा से बेहतर करने कोशिश की है। मोदी भी इसकी अहमियत को अच्छी तरह समझते है शायद यही कारण है कि मोदी ने शपथग्रहण समारोह में शार्क देशों को न्योता भेजा। मोदी की प्राथमिकता थी पहले शार्क देशों से संबंध बेहतर किये जाए। कई सालों से रुकी बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। इस मुलाकात में नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत में भले ही दोनों देशों के गंभीर मुद्दों पर ना हुई हो लेकिन व्यक्तिगत तौर पर दोनों का मातृत्व प्रेम बेहद चर्चा में रहा।

मोदी ने नवाज की मां के लिए शाल भेजा तो जवाब में नवाज ने मोदी की मां के लिए सफेद रंग की शानदार साड़ी भेजी। दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच तोहफे की लेनदेने ने दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत किये। लेकिन तोहफा मिलने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान सरकार की नीयत पर एक सावलिया निशान खड़ा करता है। पाकिस्तान कई बार अपने वादे से मुकरता आया है। भारत की तरफ से की गयी हर कोशिश पाकिस्तान की इस चाल के कारण नाकाम रह जाता है। हालांकि सीजफायर को लेकर सरकार कई बार अपना विरोध जता चुकी है लेकिन इन विरोधों का पाकिस्तान पर कोई खास असर नहीं पड़ा। दरअसल वहां की राजनीति व विदेश निति में आइएसआई का सीधा हस्तक्षेप है। इसलिए वहां की सरकार की कथनी और करनी में हमेशा अंतर दिखता है। बल्कि हाफिज

सईद– वेद प्रताप वैदिक प्रकरण के बाद मंगलावर को एक पाकिस्तान टीवी के पत्रकार ने जिस तरह से अपने बयानों के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश की इससे यह संकेत भी मिलता है कि वहां की सरकार के साथ मीडिया पर भी तो आइएसएसआई व अतिवादी संगठनों का प्रभाव तो नहीं है।अब जब देश में हंगामा मचा है, तो मोदी के स्वदेश वापसी के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या रुख रहेगा।

1.7 चीन के साथ संबंध बेहतर करने की चुनौती

भारत और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते को भारत और मजबूत करना चाहता है। चीन में भी भारत की कई कंपनियां निवेश कर रही है। नरेंद्र मोदी के पास भारत और चीन के संबंधो को लेकर जो सबसे बड़ी चुनौती है वह सीमा विवाद की। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है। इसके अलावा भारत के सीमा क्षेत्र में कई बार कैंप बना चुका है। ब्राजील में दोनों देश करीब आये।

यहां दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। शी चिनपिंग के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद सफल करार दिया। शायद इस बात का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि मुलाकात के लिए जहां 40 मिनट का वक्त मुकर्रर था, वहीं यह मुलाकात तकरीबन 80 मिनट तक चली। इस दौरान सीमा विवाद से लेकर द्विपक्षीय व्यापार और ब्रिक्स बैंक जैसे तमाम मुद्दों पर बात हुई। इस मुलाकात में मोदी ने शी चिनपिंग से कई मुद्दों पर बातचीत की दोनों पक्ष सीमा संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए 17 दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता कर चुके हैं। भारत का कहना है कि यह विवाद 4,057 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़ा है जबकि चीन का दावा है कि यह केवल अरुणाचल प्रदेश के 2,000 किलोमीटर क्षेत्र तक सीमित है, जिसे वह दक्षिणी तिब्बत करार देता है। बैठक के दौरान मोदी ने यह सुझाव भी दिया कि तिब्बत स्थित कैलास मानसरोवर के लिए यात्रा के एक और मार्ग की व्यवस्था की जाए क्योंकि यह क्षेत्र बेहद दुर्गम है। इस यात्रा में 19,500 फुट की बेहद मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है हालांकि चीन के राष्ट्रपति ने इस पर कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी पर उनकी इन मांगों पर गौर करन

की बात जरुर कही। ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकी भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते पर गहरा असर करेगी।

1.8 जापान से नजदीकी बढ़ाने की चुनौती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान से नजदीकी बढ़ाने की भी कोशिश में है। जापान भी भारत से व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। जापान भारत में उसी पैमाने पर निवेश करना चाहता है जैसा कि 80 और 90 के दशक में उसने चीन में किया था। अब चीन के साथ तनातनी के माहौल में जापान भारत में एक कारगर आप्शन देख रहा है। भारत भी जापान के साथ संबंधो को बेहतर करके चीन को साधना चाहता है। जापान अच्छी तरह जानता है कि भारत में उसके निवेश से जापान की आर्थिक व्यवस्था में सुधार संभव है। पीएम नरेंद्र मोदी को जुलाई के पहले हफ्ते में जापान टूर पर जाना था। लेकिन उससे पहले जापानी उद्योग जगत ने भारत के सामने कुछ मांगें रख दी। भारत के साथ आर्थिक रिश्ते गहरे करने के लिए उसने जापानी उद्योग प्रतिनिधियों और स्टाफ के लिए वीजा पालिसी को उदार बनाने और वहां के वकीलों को भारत में काम करने की इजाजत देने की मांग की है, ताकि जापानी इनवेस्टर्स और प्रफेशनल्स का भारत पर भरोसा गहरा हो सके। भारत भी जापान के साथ बेहतर संबंध की उम्मीद करता है।

1.9 अमेरिका और रुस को एक साथ साधने की कोशिश

नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका और रुस के साथ रिश्तों को मबजबू करने की चुनौती है। दोनों देशों को भारत एक साथ साधना चाहता है। अमेरिका भारत के नये प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उतावला है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया। भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने के संकेत देने के लिए ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 मई, 2014 के बाद से अब तक अपने दो उच्चस्तरीय नुमाइंदों को भारत भेज चुके हैं। मोदी की अमेरिका यात्रा भी 30 सितंबर को तय हो गई है। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच होने वाली रणनीतिक वार्ता की जमीन तैयार करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री जान कैरी ने भी मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया। अमेरिका के

इन प्रयासों से स्पष्ट है कि भारत के साथ व्यापारिक और राजनीतिक संबंध भी बेहतर करने के लिए अमेरिका उत्सुक है। दूसरी तरफ रुस भी भारत के साथ होते प्रगाड़ संबधों को लेकर खुशी जता चुका है। प्रधानमंत्री ने रुस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने रुस के साथ रक्षा एवं ऊर्जा क्षेत्रों में विशेष रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने की पैरवी की है। इसके साथ उन्होंने रुसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन को आगामी दिसंबर में होने वाली उनकी भारत यात्रा के दौरान कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। मोदी ने भी रुस को एक अच्छा दोस्त बताया उन्होंने कहा कि हम रुस के साथ हुई दोस्ती का बेहद सम्मान करते है। कुल मिलाकर इन दोनों देशों के साथ रिश्ते बेहतर करने और इन देशों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है।

1.10 बांग्लादेश और श्रीलंका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों को भारत के करीब लाने की है। भारत औ बांग्लादेश के बीच चला आ रहा समुद्री विवाद भी खत्म हो गया। संयुक्त राष्ट्र के एक न्यायाधिकरण ने विवादित क्षेत्र का लगभग 80 फीसदी हिस्सा बांग्लादेश को देने का फैसला किया है। फैसले के तहत दोनों देशों के बीच विवाद में फँसे बंगाल की खाड़ी के 25,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके का 19,500 किमी। का क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया है और करीब छह हजार किमी। का क्षेत्र भारत के हिस्से में आया है। इसके अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी इन दो देशो के बीच रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश में है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को क्रीम कलर की साड़ी भेंट की, वहीं हसीना ने बदले में भारतीय नेता को बांग्लादेश की प्रसिद्ध जामदानी साड़ी तोहफे में दी। दूसरी तरफ भारत श्रीलंका से रिश्ते सुधारने के लिए नाराज तमिल लोगों को मानने की कोशिश कर रहा है। मोदी के शपथग्रहण समारोह में तमिल श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की उपस्थिति इन दोनों देशों के रिश्ते को बेहतर होते रिश्ते का सबूत है।

आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत का नेतृत्व कर रहा है। 50

करोड़ से अधिक भारतीयों को कवर करते हुए आयुष्मान भारत गरीब और नव–मध्यम वर्ग को उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर रहा है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य पत्रिकाओं में से एक लांसेट ने आयुष्मान भारत की सराहना करते हुए कहा है कि यह योजना भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े असंतोष को दूर कर रही है। पत्रिका ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राथमिकता देने के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की भी सराहना की। देश की वित्तीय धारा से दूर गरीबों को वित्तीय धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय का बैंक खाते खोलना था। अब तक 35 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों ने न केवल गरीबों को बैंक से जोड़ा, बल्कि सशक्तीकरण के अन्य रास्ते भी खोले हैं।

जन–धन से एक कदम आगे बढ़ते हुए श्री मोदी ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को बीमा और पेंशन कवर देकर जन सुरक्षा पर जोर दिया। जन धन– आधार– मोबाइल) ने बिचौलियों को समाप्त कर दिया है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की है। असंगठित क्षेत्र से जुड़े 42 करोड़ से अधिक लोगों के पास अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत पेंशन कवरेज मिली है। 2019 के चुनाव परिणामों के बाद पहली कैबिनेट बैठक के दौरान व्यापारियों के लिए समान पेंशन योजना की घोषणा की गई है। 2016 में गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। यह योजना 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को धुआं मुक्त रसोई प्रदान करने में एक बड़ा कदम साबित हुई है। इसकी अधिकांश लाभार्थी महिलाएं हैं।

आजादी के बाद से 70 वर्षों के बाद भी 18,000 गाँव बिना जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाई गई है। श्री मोदी का मानना है कि कोई भी भारतीय बेघर नहीं होना चाहिए और इस विजन को साकार करने के लिए 2014 से 2019 के बीच 1 ।25 करोड़ से अधिक घर बनाए गए है। 2022 तक प्रधानमंत्री के 'हाउसिंग फार आल' के सपने को पूरा करने के लिए घर के निर्माण की गति में तेजी आई है।

कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो श्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब है। 2019 के अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में एक मौद्रिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। 24 फरवरी 2019 को योजना के शुरू होने के बाद लगभग 3 सप्ताह में नियमित रूप से किश्तों का भुगतान किया गया है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान इस योजना में 5 एकड़ की सीमा को हटाते हुए सभी किसानों को पीएम किसान का लाभ देने का फैसला किया गया। इसके साथ ही भारत सरकार प्रति वर्ष लगभग 87,000 करोड़ रुपये किसान कल्याण के लिए समर्पित करेगी। श्री मोदी ने सायल हेल्थ कार्ड, बेहतर बाजारों के लिए ई–नाम और सिंचाई पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने जैसी किसान कल्याण की दिशा में विभिन्न पहल शुरू की। 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री ने जल संसाधनों से संबंधित सभी पहलुओं की देखरेख करने के लिए एक नया जल शक्ति मंत्रालय बनाकर एक बड़ा वादा पूरा किया।

2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 'स्वच्छ भारत मिशन' शुरू किया। इस जन आंदोलन का बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक प्रभाव पड़ा है। 2014 में स्वच्छता कवरेज 38: थी जो आज बढ़कर 99: हो गई है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। स्वच्छ गंगा के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छ भारत मिशन की सराहना की और कहा कि इससे 3 लाख लोगों की जान बच सकती है। श्री मोदी का मानना है कि परिवहन परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है। इसीलिए भारत सरकार हाई–वे, रेलवे, आई–वे और वाटर–वे के रूप में अगली पीढ़ी के बुनियादी

ढाँचे को बनाने के लिए काम कर रही है। UDAN (उड़े देश के आप नागरिक) योजना ने उड्डयन क्षेत्र को लोगों के अधिक अनुकूल बनाया है और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है।

पीएम मोदी ने भारत को अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण पावर हाऊस में बदलने के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की। इस प्रयास से परिवर्तनकारी परिणाम सामने आए हैं। उदाहरण के लिए 2014 में मोबाइल

विनिर्माण इकाइयों की संख्या 2 थी जो 2019 में बढ़कर 122 हो गई है। भारत ने 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' में महत्वपूर्ण प्रगति की है, 2014 में भारत की रैंकिंग 142 थी 2019 में यह 77 हो गई है। 2017 में संसद के एक ऐतिहासिक सत्र के दौरान भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया, जिसने 'वन नेशन, वन टैक्स' के सपने को साकार किया।

उनके कार्यकाल में भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू 'स्टैच्यू आफ यूनिटी' बनाया गया जो सरदार पटेल को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। इस स्टैच्यू को एक विशेष जन आंदोलन के माध्यम से बनाया गया था, जिसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों के औजार और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था, जो 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से गहरा लगाव है। उन्हेंने हमेशा से पाना है कि हमें एक साफ और हरा ग्रह बनाने के लिए काम करना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन के अभिनव समाधान तैयार करने के लिए अलग जलवायु परिवर्तन विभाग बनाया। इस भावना को पेरिस में 2015 के COP21 शिखर सम्मेलन में भी देखा गया था जहां पीएम मोदी ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जलवायु परिवर्तन से एक कदम आगे बढ़कर पीएम मोदी ने जलवायु न्याय के बारे में बात की है। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे। यह गठबंधन एक बेहतर ग्रह के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक अभिनव प्रयास है।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके प्रयासों को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र के 'चौंपियंस आफ अर्थ अवार्ड' से सम्मानित किया गया। जलवायु परिवर्तन ने हमारे ग्रह को प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त कर दिया है, इस तथ्य के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील होते हुए श्री मोदी ने प्रौद्योगिकी की शक्ति और मानव संसाधनों की ताकत के उचित इस्तेमाल के रूप में आपदा के लिए एक नया विजन साझा किया है । मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 26 जनवरी 2001 को विनाशकारी भूकंप से तबाह हुए गुजरात को बदल

दिया। इसी तरह उन्होंने गुजरात में बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए नई प्रणालियों की शुरुआत की जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई।

प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से श्री मोदी ने नागरिकों के लिए न्याय को हमेशा प्राथमिकता दी है। गुजरात में लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने शाम की अदालतों की शुरुआत की। केंद्र में उन्होंने PRAGATI (प्रो–एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) शुरू किया जो विकास में देरी कर रहे लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए एक कदम है।

श्री मोदी की विदेश नीति की पहल ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता और भूमिका को महसूस किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों के सभी प्रमुखों की उपस्थिति में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया और दूसरे की शुरुआत में बिम्सटेक नेताओं को आमंत्रित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके संबोधन की दुनिया भर में सराहना हुई। पीएम मोदी 17 साल की लंबी अवधि के बाद नेपाल, 28 साल के बाद आस्ट्रेलिया, 31 साल के बाद फिजी और 34 साल के बाद सेशेल्स और यूएई के द्विपक्षीय दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।

प्रधानमंत्री को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'किंग अब्दुलअजीज सैश' से सम्मानित किया गया। श्री मोदी को रूस के शीर्ष सम्मान 'द आर्डर आफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टले सम्मान', फिलिस्तीन के 'ग्रैंड कालर आफ द स्टेट आफ फिलिस्तीन' सम्मान, अफगानिस्तान के 'अमीर अमानुल्ला खान अवार्ड', यूएई के 'जायेद मेडल' और मालदीव के 'निशान इज्जुद्दीन' सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को शांति और विकास में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार दिया गया। 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाने के नरेंद्र मोदी के आग्रह को संयुक्त राष्ट्र में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। पहले दुनिया भर में कुल 177 राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर 21 जून को संयुक्त राष्ट्र में 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। **1.11 भारत–पाक संबंध और बाधाएँ**

नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों को अपनी विदेश नीति में शीर्ष प्राथमिकता पर रखा

है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के साथ भारत का विभिन्न मुद्दों पर विवाद है, जैसे– कश्मीर, सियाचिन, सिंधु नदी जल विवाद, कच्छ का रण या सरक्रीक विवाद। वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री ने लाहौर की यात्रा की, किंतु पठानकोट हमला और सीमा–पार आतंकवाद के कारण संबंधों में गतिरोध उत्पन्न हुआ। इसी क्रम में 'सर्जिकल स्ट्राइक' और भारत ने पाकिस्तान में आयोजित 'सार्क सम्मेलन' का बहिष्कार किया।

चीन ने पाकिस्तान में 'ग्वादर पत्तन' का निर्माण किया है। चीन के द्वारा 'वन रोड वन बेल्ट' परियोजना के अंतर्गत 'चीन पाकिस्तान–आर्थिक' गलियारा का निर्माण किया जा रहा है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर जा रहा है, जिसे भारत अपना क्षेत्र मानता है। इस क्षेत्र में चीनी अधिकारियों और सैनिकों को तैनात किया जा रहा है जो भारतीय सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा साबित हो सकता है। इसके अतिरिक्त चीन–रूस संबंधों के कारण पाकिस्तान की रूस के साथ भी नजदीकियाँ बढ़ रही हैं। चीन–पाकिस्तान–रूस संबंधों के कारण भारतीय हित प्रभावित हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की नजर में पड़ोसी देशों की अहमियत स्पष्ट है। पिछले नेताओं के विपरीत वह घरेलू व्यापार में वृद्धि और विकास के लिये विदेशी निवेश, व्यापार और प्रौद्योगिकी हासिल करने के साधन के रूप में विदेश नीति का उपयोग करने के लिये उत्सुक हैं। लेकिन यह एक कठिन और जटिल कार्य होगा, विशेष रूप से भारत के दो शक्तिशाली परमाणु–शस्त्र संपन्न पड़ोसी देशों, पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध राजनीतिक और सैन्य गतिरोधों के कारण तनावपूर्ण रहे हैं। वर्तमान में पाकिस्तान, भुगतान संतुलन जैसे संकट का सामना कर रहा है और पाकिस्तान पर ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास में भारत सहयोगी की भूमिका निभा सकता है।

हाल ही में पाकिस्तानी प्रशासन ने 'करतारपुर कारिडोर' बनाने का ऐलान किया है जिसका भारत ने समर्थन किया। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही नागरिकों के मध्य संपर्क अर्थात् 'पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट' होगा तथा संबंधों में मधुरता तथा विश्वास बढ़ने की उम्मीद है।

1.12 भारत–चीन संबंध और बाधाएँ

प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का एहसास है कि तेजी से आर्थिक विकास के अपने घरेलू एजेंडे को स्थिर और अनुकूल पड़ोसियों को साथ लिये बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती पैठ को लेकर भी भारत सतर्क है। हालाँकि इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति भारत द्वारा पूरी तरह से टालने योग्य या अवांछनीय नहीं है, लेकिन भारत की कुछ रणनीतिक चिंताएँ जरूर हैं। चीन ने 'वन बेल्ट वन रोड' जैसी परियोजनाओं के माध्यम से दक्षिण एशियाई देशों में अपनी साफ्ट पावर को बढ़ाया है। भारत के चारों ओर रणनीतिक स्थानों तथा हिंद महासागर के महत्त्वपूर्ण संचार मार्गों पर चीन लगातार बुनियादी ढाँचे, विशेष रूप से बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है और दक्षिण

एशिया में भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है जिसे अक्सर घेरने की रणनीति या श्मोतियों की माला कहा जाता है।

चीन ने पाकिस्तान के सदाबहार मित्र के रूप में उभरने के अलावा, भारत के अधिकांश पड़ोसियों पर गहरी पकड़ बनाई है। चीन ने हाल ही में जिबूती में सैनिक अड्डे का निर्माण किया है। भारत के द्वारा चीन के साथ 'डीलिंकिंग' की नीति को अपनाया गया है, जिसके तहत आर्थिक संबंधों और सीमा विवाद को अलग–अलग देखने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में भारत–चीन द्वीपक्षीय व्यापार लगभग 76 बिलियन डालर का हो गया है। भारत का सबसे बड़ा द्वीपक्षीय भागीदार चीन है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिये भारत ने सामरिक और प्रैग्मैटिक नीति के तहत 'मालाबार सैन्य अभ्यास' में जापान को सम्मिलित किया, तो वहीँ क्वैड (अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया, भारत) में शामिल हुआ। दोनों देशों के मध्य अनेक क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएँ हैं। हाल की वार्ताओं में दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत–चीन संबंधों को नया आयाम दिया जाए।

1.13 पाकिस्तान एक कठिन चुनौती

आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तीन युद्ध कश्मीर को लेकर और एक बांग्लादेश को लेकर लड़े गए। 1998 में जब दोनों देशों ने परमाणु हथियार हासिल कर लिये तब से यह कम तीव्रता वाले

सैन्य टकराव में बदल गया। विवादित कश्मीर क्षेत्र को विभाजित करने वाली नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा हिंसा और गोलीबारी के कारण द्विपक्षीय शांति वार्ता को अंजाम तक ले जाना मोदी सरकार के लिये बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों लश्कर–ए–तैयबा या जैश–ए–मोहम्मद ने 2008 में जिस तरह से मुंबई हमले को अंजाम दिया था वैसे हमले पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह ही कर सकते हैं।

भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों का मानना है कि इस तरह के किसी भी हमले की योजना पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान द्वारा विशेष रूप से अपने शक्तिशाली खुफिया संगठन, इंटर–सर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा बनाई जाती है। मोदी ने पाकिस्तान के प्रति भारत के रुख को सख्त कर दिया है। उन्होंने भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त और कश्मीरी अलगाववादी हुर्रियत संगठन के बीच अगस्त 2014 में निर्धारित विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द कर दिया। इसके साथ ही भारत ने भी जान–बूझकर नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग तेज कर दी है। हालाँकि इससे भारत को अधिक लाभ नहीं मिला है। पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने तथा आपसी विश्वास हासिल करने के लिये भारत को कुछ हट कर सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान की नागरिक सरकार को मजबूत करने के साथ–साथ भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान की सेना के साथ जुड़ने की जरूरत है ताकि यह पता लगाया जा सके है कि भारत के प्रति उसकी मंशा क्या है।

पाकिस्तान की आर्मी भारत के साथ शत्रुता की नीति को नहीं त्यागना चाहती है और कायरतापूर्ण हमले रोकने की इच्छुक नहीं दिखाई देती लेकिन जब तक ऐसी दुर्भावनाओं को रोका नहीं जाता, सार्थक वार्ता हो पाना संभव नहीं है। सरकार ने अब तक के कार्यकाल में संबंधों को पटरी पर लाने के लिये उचित प्रयास किये हैं। प्रधानमंत्री लाहौर तक गए लेकिन पाकिस्तान की जो नकारात्मक नीति है वह पारंपरिक है और चली आ रही है। 2016 में पठानकोट और उसके बाद उड़ी में आतंकी हमलों का कारण पाकिस्तान ही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह कहना कि बम और बंदूक की आवाज में बातचीत की प्रक्रिया नहीं हो सकती, उचित ही है। आतंकवाद और वार्ता दोनों एक साथ नहीं हो सकती। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान

पर दबाव बनाने का असर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से रखना भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकता में रहा है। इन मंचों में पाकिस्तान पर दबाव बनाने की बात की गई है जिसका असर विगत वर्षों में देखने को मिला है। अगर द्वीपक्षीय स्तर पर देखें तो आतंकवाद के मुद्दे पर सभी देश भारत के साथ आना चाहते हैं यानी भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के जो खास मित्र देश हुआ करते थे उनको भी भारत समझाने में सफल हुआ है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा तब तक पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध सुधर नहीं सकते। इससे कहीं–न–कहीं 'टर्म्स आफ इंगेजमेंट' में बदलाव आया है और पाकिस्तान अपने आपको अलग–थलग महसूस करने लगा है। पिछले ब्रिक्स सम्मेलन में पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों को लेकर उद्घोषणा की गई थी। पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग–थलग करने की मोदी सरकार की नीति उतनी सफल नहीं हो पा रही है क्योंकि इस्लामाबाद ने बीजिंग, मास्को और तेहरान को शामिल करने के लिये अपने राजनयिक प्रयास बढ़ा दिये हैं।

1.14 महान शक्तियों के साथ संबंध रूस और अमेरिका

मोदी सरकार की सबसे बड़ी विदेशी नीति सफलताएँ भारत के बाहरी संबंधों के बाहरीतम सांद्र चक्र में देखी गई हैं। □01 से, प्रशासन बड़ी शक्तियों के साथ सक्रिय रूप से संबंध बढ़ाने में लगा हुआ है, और कुछ अर्थों में, गुट निरपेक्ष नीति से दूर भी हुआ है। यह विशेष रूप से भारत–अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के मामले में सफल रहा, जहां द्विपक्षीय भागीदारी के मामले में दोनों पक्षों ने इतिहास के बोझ को उतार फेंका और रक्षा सहयोग, आधारभूत लौजिस्टिकल समझौतों और भारत–प्रशांत क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर सामान्य समझ पर पहुंचने में प्रगति दिखाई। दोनों पक्षों के बीच संबंध साझा हितों के कारण बढ़े हैं और आशा है कि भविष्य में भी ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन रूस के साथ संबंध बिगड़ गए हैं क्योंकि भू–राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के कारण भारत अमेरिका संबंध घनिष्ठ हुए हैं, विशेष रूप से रक्षा

मामलों में, और रूस ने चीन और पाकिस्तान के संबंध बढ़े हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. वीर, गौतम, महाशक्तियों की विदेश नीति, पब्लिकेशन, मैक मिलन पब्लिशर्स इण्डिया लि0, दिल्ली, संस्करण–2013
2. खन्ना, वी0एस0, अन्तर्राष्ट्रीय विकास, पब्लिकेशन, हाउस प्रा0लि0 नोएडा, नई दिल्ली, पंचम संस्करण–2014
3. पंज, पुष्पेश जैन, श्रीपाल, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध सिद्धान्त और व्यवहार, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, संस्करण 2014–15

4. जौहरी, जे0सी0, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा राजनीति, स्टलिंग पब्लिशर्स प्रा0 लिमिटेड, संस्करण–2011

5. दत्त, वी0पी0, स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति, पब्लिकेशन, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नेहरू भवन, नई दिल्ली, संस्करण–2011

6. पंत, पुष्पेश, भारत की विदेश नीति, पब्लिकेशन, टाटा मेग्रा हिल, नई दिल्ली, संस्करण–2010 7. वर्ल्ड फोकस, भारत की विदेश नीति, भाग–2, अंक–71, संस्करण–फरवरी, 2018

8. वर्ल्ड फोकस, भारत की विदेश नीति, भाग–1, अंक–70 संस्करण–जनवरी, 2018

9. वैदिक, डॉ0 वेद प्रताप, मोदी की विदेशी नीति वैदिक की नजर में, पब्लिकेशन डायमण्ड पॉकेट बुक्स प्रा0लि0, नई दिल्ली।

10. पंत, पुष्पेश,21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, पब्लिकेशन टाटा मेग्राहिल, नई दिल्ली, संस्करण– 2014

11. फाईमा, बी0एल0, भारत एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, पब्लिकेशन साहित्य भवन, आगरा, संस्करण–2015